योजना का सारांश (जुलाई 2026)

1. सांस्कृतिक विरासत और भारत का सभ्यतागत पुनर्जागरण

परिचय

भारत का सभ्यतागत पुनर्जागरण विरासत को शासन, शिक्षा, पर्यटन एवं कूटनीति के साथ एकीकृत करता है जिससे राष्ट्र निर्माण और सतत विकास को समर्थन मिलता है। आयुर्वेद, बौद्ध धर्म, पारंपरिक चिकित्सा और भारतीय दर्शन G 20 (ग्रुप ऑफ ट्वेंटी) और वैश्विक मंचों के माध्यम से सॉफ्ट पावर को अधिक मजबूत करते हैं।

सभ्यतागत दृष्टिकोण एवं लोकतांत्रिक संस्थाएँ

- 'विकास भी, विरासत भी' पहल आधुनिकीकरण को विरासत के साथ जोड़ती है और संस्कृति को विकास के बुनियादी ढाँचे का हिस्सा मानती है।
- आजादी के 75वें वर्ष में बताए गए 'पंच प्रण' ने औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति और विरासत पर गर्व को राष्ट्रीय संकल्प बनाया।
- नवीन संसद भवन के गज-द्वार, अश्व-द्वार, गरुड़-द्वार, हंस-द्वार, मकर-द्वार और शार्दुल-द्वार सभ्यतागत प्रतीकवाद को समाहित करते हैं।
- संविधान गैलरी वेदों, महाकाव्यों, प्राचीन संस्थाओं, शिलालेखों व पांडुलिपियों का हवाला देते हुए भारत को 'लोकतंत्र की जननी' के रूप में प्रस्तुत करता है।
- सेंगोल चोल काल की सत्ता हस्तांतरण और स्वतंत्रता की परंपराओं को पुनर्जीवित करता है और धर्म-निर्देशित शासन को समकालीन लोकतंत्र से जोड़ता है।
- कर्त्तव्य पथ और सेवा तीर्थ ने कर्त्तव्य, सेवा और सार्वजनिक जिम्मेदारी के इर्द-गिर्द राज्य संस्थाओं को नया रूप दिया है।

ज्ञान संरक्षण और सांस्कृतिक भागीदारी

- ज्ञान भारतम् मिशन (Gyan Bharatam Mission) पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण कर उन्हें डिजिटल भंडारों (Repositories) में संरक्षित करता है जबकि नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार एशिया-पार विद्वत्ता, संवाद और ज्ञान-सृजन की परंपरा को पुनर्स्थापित करता है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 भारतीय ज्ञान प्रणालियों को एकीकृत करती है जबकि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ONOS) के माध्यम से शोध एवं अकादमिक संसाधनों तक समान और व्यापक पहुँच सुनिश्चित की गई है।
- सांस्कृतिक मानचित्रण पर राष्ट्रीय मिशन और 'मेरा गाँव मेरी धरोहर' नामक दस्तावेज सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से गाँवों की जीवंत परंपराओं को दर्शाते हैं।
- युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय तथा प्रधानमंत्री संग्रहालय संग्रहालयों को आधुनिक, सहभागितापूर्ण और नागरिक-केंद्रित सांस्कृतिक स्थलों के रूप में विकसित करते हैं।
- एक भारत श्रेष्ठ भारत और काशी तमिल संगमम एकीकरण को मजबूत करते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वैश्विक सॉफ्ट पावर का विस्तार करता है।

पवित्र विरासत और वैश्विक पहचान

- काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, महाकाल लोक, केदारनाथ पुनर्निर्माण, अयोध्या और राम मंदिर ने पवित्र स्थलों को नया रूप दिया है।
- तीर्थयात्रा कायाकल्प एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (PRASHAD) एवं 'स्वदेश दर्शन' जैसी योजनाओं ने संरक्षण, पर्यटन, रोजगार व समुदाय की भागीदारी को एक साथ जोड़ा है।
- श्रीपुरंथन नटराज प्रतिमा, माँ अन्नपूर्णा देवी प्रतिमा और चोल तांबे की प्लेटों सहित 600 से अधिक प्राचीन कलाकृतियों की वापसी ने देश की सांस्कृतिक संरक्षण को मजबूती प्रदान की है।
- पिपरहवा से मिले भगवान बुद्ध के अवशेष वापस लाए गए और 'द लाइट एंड द लोटस' प्रदर्शनी के जरिए किला राय पिथोरा में प्रदर्शित किए गए।
- यूनेस्को ने योग, दीपावली, भगवद्गीता व भरतमुनि के नाट्यशास्त्र को अपनी सूची में शामिल करके हमारी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को मान्यता दी है।
- भारत मंडपम में लगी 27 फीट ऊँची नटराज की मूर्ति जी20 के प्रतीक के तौर पर आकर्षण का केंद्र रही; साथ ही, एक्सपो 2025 ओसाका और वेनिस बिएनाले 2026 ने वैश्विक स्तर पर संवाद को आगे बढ़ाया।

निष्कर्ष

विकसित भारत@2047 के लिए, महासुभाषिता संग्रह (श्लोक 3116) पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता, प्रबंधन और नवीनीकरण का आधार बनता है।

2. भारत का लॉजिस्टिक्स भविष्य : विजन 2047

परिचय

पिछले बारह वर्षों में राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन ने भारत के परिवहन अवसंरचना को सुदृढ़ किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान ने एकीकृत, प्रौद्योगिकी-सक्षम तथा लचीली (Resilient) लॉजिस्टिक्स प्रणाली के विकास को गति प्रदान की है।

रणनीतिक महत्त्व और नेटवर्क विस्तार

- रसद परिवहन, भंडारण और मूल्यवर्धन के माध्यम से उत्पादन और उपभोग को जोड़ता है, जिससे विकास, रक्षा और लचीलेपन को मजबूती मिलती है।
- महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया संकट ने आपूर्ति शृंखला की कमजोरियों को उजागर किया, जिससे सुदृढ़ और लचीली लॉजिस्टिक्स प्रणाली आर्थिक दृष्टि से अनिवार्य बन गई।
- लगभग 100% रेलवे विद्युतीकरण, वंदे भारत ट्रेनें, अमृत भारत स्टेशन योजना, कवच (स्वदेशी ट्रेन सुरक्षा प्रणाली) तथा सोनीपत-जींद हाइड्रोजन ट्रेन परियोजना के साथ जम्मू-कश्मीर और मिजोरम तक रेलवे संपर्क का विस्तार किया गया है।
- रेल माल ढुलाई से होने वाली आय 2013-14 में 93,400 करोड़ रुपये से बढ़कर 1.78 लाख करोड़ रुपये हो गई, जो लगभग 90% की वृद्धि है और क्षमता को मजबूत करती है।
- समर्पित मालवाहक गलियारे की कुल लंबाई 2,843 किलोमीटर है। अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना का 508 किलोमीटर लंबा मार्ग 320 किमी/घंटा की गति से संचालित होगा, जिसका पहला चरण 2027 तक शुरू होने का लक्ष्य है।
- भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 22,500 से अधिक किलोमीटर सड़क नेटवर्क का विकास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 1.46 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग तथा 3,052 से अधिक किलोमीटर एक्सप्रेसवे विकसित किए गए हैं, जिनमें दिल्ली-देहरादून और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे प्रमुख हैं।

बहुआयामी अवसंरचना और क्षमता

- वर्ष 2014 में 74 से बढ़कर 2026 तक 165 हवाई अड्डों का विकास किया गया। उड़ान योजना, C-295 विमान असेंबली, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तथा नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जैसी परियोजनाओं ने देश की विमानन क्षमता को सुदृढ़ किया।
- वधावन बंदरगाह, सागरमाला परियोजना तथा समुद्री विकास कोष ने बंदरगाह अवसंरचना को मजबूती प्रदान की, जबकि भारत के नौ बंदरगाह वैश्विक शीर्ष-100 बंदरगाहों में शामिल हुए।
- राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 5 से बढ़कर 111 हो गई। जलमार्गों के माध्यम से माल परिवहन 2014 के 18.1 मिलियन टन से बढ़कर 2025 में 145.5 मिलियन टन हो गया। लगभग 5,000

किलोमीटर जलमार्ग परिचालन के माध्यम से 35 लाख यात्रियों को सेवाएँ प्रदान की गईं।

- मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार 26 शहरों में 1,155 किलोमीटर तक हो चुका है। इसके साथ ही क्षेत्रीय तीव्र परिवहन प्रणाली (RRTS), बस रैपिड ट्रांजिट (BRT) तथा फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME) जैसी पहलों ने शहरी गतिशीलता (Urban Mobility) को नई गति दी है।
- 35 मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, 306 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, इनलैंड कंटेनर डिपो (ICDs) तथा गति शक्ति विश्वविद्यालय ने देश की बहु-माध्यमीय लॉजिस्टिक्स क्षमता को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ किया है।
- तापमान नियंत्रित गोदाम मानक सुविधाओं की लागत लगभग दोगुनी होती है, जबकि खतरनाक माल ढुलाई के लिए सुरक्षा, विनियामक और बुनियादी ढाँचे से संबंधित लागत अधिक होती है।

डिजिटल एकीकरण और विजन 2047

- प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत 3,200 से अधिक डेटा लेयर को 58 मंत्रालयों तथा 36 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से एकीकृत किया गया है। इसके माध्यम से ₹15 लाख करोड़ से अधिक मूल्य की 240 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया।
- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, 2022 तथा यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मानकों, ट्रैकिंग, डेटा साझाकरण तथा आधारित परियोजना क्रियान्वयन को एकीकृत किया गया है।
- लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक 100% निर्यात-आयात कंटेनरों पर नजर रखता है, जबकि विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स की सुगमता सहकारी संघीय प्रदर्शन का मानक निर्धारित करती है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रेडियो-फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, जीपीएस और फास्टैग ट्रैकिंग जैसी तकनीक माल की ट्रैकिंग तथा पूर्वानुमान-आधारित रखरखाव (Predictive Maintenance) को सक्षम बनाती हैं।
- केंद्रीय बजट 2026 में 2,150 किलोमीटर लंबे दानकुनी-सूरत तृतीय समर्पित मालवाहक गलियारे (Third Freight Corridor) तथा सात हाई-स्पीड रेल ग्रोथ कनेक्टर्स की घोषणा की गई। साथ ही 596 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास और क्षेत्रीय संपर्क को सुदृढ़ करेगा।

निष्कर्ष

विकसित भारत@2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भूमि उपयोग, औद्योगिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा हरित (Green) बहु-माध्यमीय परिवहन योजना के बीच समन्वित दृष्टिकोण आवश्यक है, जो नेट जीरो 2070 के लक्ष्य के अनुरूप हो। नीदरलैंड की डिजिटल लॉजिस्टिक्स प्रणाली तथा चीन के अवसंरचना-औद्योगिक समन्वय से यह स्पष्ट होता है कि अवसंरचना का उद्देश्य केवल निर्माण नहीं, बल्कि उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और सतत आर्थिक विकास को गति देना होना चाहिए।

3. उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए दीर्घकालिक रणनीतिक ढाँचा

परिचय

मध्य पूर्व संकट के बीच भारत की उर्वरक आत्मनिर्भरता रणनीति में वैकल्पिक उत्पादन, संतुलित उपभोग और प्राकृतिक खेती का संयोजन शामिल है।

आयात पर निर्भरता और स्थिरता संबंधी चिंताएँ

- आर्थिक सर्वेक्षण, 2025-26 के अनुसार प्रौद्योगिकी, सिंचाई और उर्वरकों के सहयोग से पाँच वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र में 4% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है।
- रासायनिक उर्वरकों की अत्यधिक मात्रा मिट्टी की उर्वरता को कमजोर करती है। साथ ही, नाइट्रोजन उपयोग दक्षता (एनयूई) में गिरावट के कारण अधिक मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करने पर भी पैदावार में सीमित वृद्धि होती है।
- यूरिया और डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) की स्थिर कीमतें किसानों को सुरक्षा प्रदान करती हैं लेकिन उर्वरक सब्सिडी वैश्विक मूल्य उतार-चढ़ाव के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है।
- देश में यूरिया की वार्षिक मांग 39 मिलियन टन के करीब है, जबकि घरेलू उत्पादन लगभग 31 मिलियन टन तक पहुँचता है। इस कारण यूरिया का आयात अपरिहार्य बना रहता है।
- घरेलू यूरिया उत्पादन आयातित प्राकृतिक गैस पर निर्भर है, जबकि डीएपी की लगभग 60% आवश्यकता आयात से पूरी होती है। इसके अतिरिक्त, देश में डीएपी का उत्पादन भी मुख्यत: आयातित कच्चे माल पर आधारित है।

वैकल्पिक उत्पादन और स्वदेशी समाधान

- तीन प्रमुख रणनीतियाँ जलवायु-सहिष्णु कृषि के लिए गैर-जीवाश्म आधारित उर्वरक उत्पादन, प्रभावी स्वदेशी विकल्पों तथा उर्वरकों के संतुलित उपयोग को प्राथमिकता देती हैं।
- राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन का लक्ष्य, 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण क्षमता विकसित करना है। इसके लिए 3,750 करोड़ की सहायता सतही (Surface) गैसीकरण परियोजनाओं हेतु प्रदान की गई है।
- कोयला गैसीकरण पेट्रोलियम गैस के बिना अमोनिया का उत्पादन कर सकता है जिससे तैयार उत्पादों व आयातित कच्चे माल पर निर्भरता कम हो जाती है।
- ग्रीन अमोनिया में लगभग 82% नाइट्रोजन होता है। इसके मशीनीकृत कृषि अनुप्रयोग के लिए मानकीकृत परीक्षण और विस्तार सहायता की आवश्यकता होती है।

- स्वदेशी नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा फसल-विशिष्ट प्रतिस्थापन प्रोटोकॉल के लिए परीक्षण किया जा रहा है।
- प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन क्षेत्र-विशिष्ट प्रोटोकॉल, प्रमाणीकरण और कम रासायनिक मात्रा के साथ मिश्रित पद्धति को विकसित करता है।

मांग प्रबंधन एवं डिजिटल सुधार

- 26 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को पोषक तत्वों की कमी के आधार पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जिससे संतुलित उर्वरक उपयोग और किसानों के व्यावहारिक में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है।
- खाद्य तेल (Edible Oil) और दलहन मिशनों के माध्यम से धान, गन्ना और गेहूँ जैसी फसलों के स्थान पर विविधीकरण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर तुअर, उड़द और मसूर की सरकारी खरीद सुनिश्चित की जा रही है।
- कृषि स्टैक के अंतर्गत 9.5 करोड़ किसान पहचान पत्र तैयार किए जा चुके हैं तथा फसल सर्वेक्षण अंतर्गत 640 जिलों और 24 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में फैले 30 करोड़ भूखंडों को शामिल किया गया है।
- कृषि स्टैक एकीकरण से उर्वरकों की कालाबाजरी और धन के दुरुपयोग पर अंकुश लग सकता है। साथ ही, बिना किसी रोक-टोक के वितरण नियमों में संशोधन किया जा सकता है और भूमिधारकों या अधिकृत प्रतिनिधियों को लक्षित किया जा सकता है।
- ICAR एवं कृषि विज्ञान केंद्रों को 2-5 हेक्टेयर के प्रदर्शन, स्वैच्छिक नैनो बिक्री और खुराक संबंधी जागरूकता कार्यक्रम चलाने चाहिए।
- डिजिटल प्रणाली के पूर्ण क्रियान्वयन के बाद ऑनलाइन मृदा परीक्षण और प्रत्यक्ष सब्सिडी में भूमि स्वामित्व, फसल, मृदा स्वास्थ्य और आईसीएआर की सिफारिशों को निर्धारित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल उत्पादन वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित वैकल्पिक उर्वरकों का प्रयोग और लक्षित एवं संतुलित उर्वरक खपत, किसानों के हित और राजकोषीय स्थिरता की रक्षा कर सकते हैं।

4. प्रकृति-अनुकूल शहरों का डिजाइन: शहरी नियोजन को प्रकृति-आधारित समाधानों पर केंद्रित करना

परिचय

सरकारें, विकास एजेंसियाँ और वित्तीय संस्थान शहरी लचीलेपन, पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली और सामाजिक समानता के लिए प्रकृति-आधारित समाधानों (NBS) को तेजी से बढ़ावा दे रहे हैं।

शहरी पारिस्थितिकी संकट और प्रकृति की भूमिका

- केरल में बाढ़, नागपुर में पानी की कमी, मुंबई में भीषण गर्मी और दिल्ली में स्कूलों का बंद होना रोजमर्रा की जलवायु संबंधी आपदाओं को दर्शाते हैं।
- तीव्र शहरी विस्तार के कारण आर्द्रभूमि और प्राकृतिक स्थानों को बंजर भूमि मानकर उन पर निर्माण किया जा रहा है, जिससे कंक्रीटीकरण, प्राकृतिक आवासों का विखंडन और वृक्षों की कटाई बढ़ रही है।
- झीलें बाढ़ नियंत्रित, भूजल पुनर्भरण और तापमान को नियंत्रित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वहीं वृक्ष और आर्द्रभूमि जैव विविधता को बनाए रखते हैं और वर्षा जल को अवशोषित करते हैं।
- पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि रामसर संरक्षित क्षेत्र, अपशिष्ट जल उपचार, मत्स्य पालन, बाढ़ अवशोषण, जैव विविधता और आजीविका को सहायता प्रदान करता है।
- संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मुंबई के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है, जबकि मैंग्रोव वन अत्यधिक वर्षा के दौरान तटीय बाढ़ और ज्वारीय लहरों के प्रभाव को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

स्थानीय समाधान और जलवायु समानता

- प्रकृति-आधारित समाधान (NBS) झीलों, आर्द्रभूमियों और हरित क्षेत्रों को पुनर्जीवित कर शहरी क्षेत्रों में जलवायु जोखिमों का समाधान प्रदान करते हैं।
- विकेंद्रीकृत एनबीएस में बायोस्वेल, रेन गार्डन, पारगम्य फुटपाथ, पुनर्स्थापित झीलें, शहरी कृषि और हरित गलियारे जैसे उपाय शामिल हैं।
- फ्लाइओवर डिवाइडर, नहरें, रेलवे बफर क्षेत्र, छतें और शैक्षणिक परिसर छोटे पारिस्थितिक बुनियादी ढाँचे के लिए उपयुक्त स्थान हो सकते हैं।
- छायादार पैदल मार्ग, बस स्टॉप और सड़क किनारे की वनस्पतियाँ न केवल रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं की रक्षा करती हैं, बल्कि आसपास के क्षेत्रों को ठंडा रखती हैं और वायु गुणवत्ता में सुधार करती हैं।
- जलवायु जोखिम का झुग्गी बस्तियों के निवासियों, सफाईकर्मियों, विक्रेताओं, डिलीवरी कर्मचारियों, मजदूरों व बुजुर्ग आबादी पर असमान रूप से प्रभाव पड़ता है।
- केवल सौंदर्यीकरण के नाम पर झीलों को घेर देना व पारंपरिक उपयोगकर्त्ताओं को बाहर करना उचित नहीं है। इसलिए एनबीएस की योजना और निर्णय प्रक्रिया में कमजोर एवं वंचित समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

योजना, विनियमन और संस्थागत सुधार

- ताप संबंधी कार्य योजनाओं में चेतावनी और सलाह को प्राथमिकता

दी जाती है, लेकिन अपर्याप्त शहरी नियोजन के कारण उत्पन्न असमान जोखिम को नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है।

- नगर निकायों के बजट में आर्द्रभूमियों, वनों और जल-पारगम्य प्राकृतिक क्षेत्रों के आर्थिक एवं पर्यावरणीय महत्त्व का पर्याप्त मूल्यांकन नहीं होता, जिसके परिणामस्वरूप बाढ़, गर्मी और अन्य आपदाओं के बाद आपातकालीन एवं प्रतिक्रियात्मक खर्च बढ़ जाता है।
- एनबीएस को निजी विकास परियोजनाओं और टाउनशिप में भवन निर्माण नियमों, योजना अनुमोदनों और शहरी डिजाइन प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना चाहिए।
- रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (RERA) विकास प्राधिकरणों और नगरपालिकाओं को देशी वृक्षों, पारगम्य सतहों व जैव विविधता गलियारों को अनिवार्य बनाना चाहिए।
- पारिस्थितिकी और विकास का समन्वय ऐसे शहरों के निर्माण में सहायक होगा जो समानतापूर्ण, मजबूत, कम लागत वाले और जलवायु-लचीले हों। जलवायु लचीलापन शहरी नियोजन का मूल सिद्धांत होना चाहिए।

निष्कर्ष

प्रकृति को बुनियादी ढाँचे के रूप में और सामाजिक समानता को नियोजन सिद्धांतों के रूप में मानने से लचीले और रहने योग्य भारतीय शहर बन सकते हैं।

5. भारत का स्वास्थ्य परिदृश्य : प्रगति एवं संभावनाएँ

परिचय

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 (NFHS-6), राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSO) का 80वाँ दौर, नमूना पंजीकरण प्रणाली (SRS) 2024 और राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (NHA) 2022-23 से पता चलता है कि स्वास्थ्य परिणामों में उल्लेखनीय सुधार के साथ-साथ प्रणालीगत असमानताएँ भी बनी हुई हैं।

मातृ, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य

- संस्थागत प्रसवों का प्रतिशत 96.2% तक पहुँच गया, जिसमें 97.8% शहरी और 95.6% ग्रामीण क्षेत्र शामिल हैं। यह मातृ स्वास्थ्य देखभाल के विस्तार और समानता को दर्शाता है।
- मातृ मृत्यु अनुपात (Maternal Mortality Ratio: MMR) घटकर 87 हो गया है। हालाँकि अंतर-राज्यीय भिन्नता असमान प्रगति व प्रणालीगत कमियों को दर्शाती है।
- गर्भनिरोधक के उपयोग की दर 69.1% तक पहुँच गई है जबकि गर्भनिरोधक साधनों की अपूर्ण आवश्यकता (Unmet Need) 9.4% से घटकर 8.5% रह गई है जिससे प्रजनन संबंधी स्वायत्तता और सक्रियता में सुधार हुआ।
- जन्म दर प्रति 1,000 जनसंख्या पर 18.3 दर्ज की गई, जबकि मिशन परिवार विकास ने साक्ष्य-आधारित योजना और सामुदायिक भागीदारी को मजबूत किया।
- पूर्ण टीकाकरण का कवरेज 87.1% तक पहुँच गया है; रोटावायरस टीके का कवरेज 36.4% बढ़कर 85.4% हो गया तथा सार्वजनिक सुविधाओं ने 95% टीकाकरण को संभव बनाया, जिससे गंभीर दस्त के मामलों में कमी आई और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर लोगों का विश्वास बढ़ा।
- शिशु मृत्यु दर घटकर प्रति 1,000 जीवित जन्म पर 24 हो गई है। वहीं अविकसित वृद्धि 35.5% से घटकर 29.3% रह गई है किंतु गंभीर क्षीणता अब भी 5.2% पर बनी हुई है, जो बाल पोषण के क्षेत्र में निरंतर प्रयासों की आवश्यकता को दर्शाती है।

गैर-संचारी रोग (NCD) और पोषण संबंधी चुनौतियाँ

- ग्रामीण क्षेत्रों में दर्ज रुग्णता दर में 6.8%-12.2% और शहरों में 9.1%-14.9% की वृद्धि हुई, जो महामारी विज्ञान संबंधी संक्रमण और स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती मांग को दर्शाता है।
- संक्रामक रोगों के मामलों में मामूली गिरावट आई, जबकि मधुमेह और हृदय रोग का बोझ तीन गुना बढ़ गया। यह भारत में गैर-संचारी रोगों के संक्रमण और निवारक देखभाल संबंधी चुनौतियों को दर्शाता है।
- 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में उच्च रक्तचाप और अनियमित ग्लूकोज स्तर, बढ़ते चयापचय संबंधी जोखिमों और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों का संकेत देते हैं।
- घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24 में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की खपत में वृद्धि दर्ज की गई है, जो आहार संबंधी बदलाव और दीर्घकालिक बीमारियों के बढ़ते जोखिम के अंतर्संबंध को दर्शाती है।
- NFHS-6 के आँकड़ों के अनुसार, 15-49 आयु वर्ग की 30.7% महिलाओं और 27.3% पुरुषों में अधिक वजन या मोटापा पाया गया है जो पोषण संक्रमण और असंतुलित आहार की समस्या को दर्शाता है।

वित्तीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य निवेश

- 2017-18 से 2025 तक सरकार द्वारा वित्तपोषित बीमा ग्रामीण क्षेत्रों में 8.9% से 31.8% और शहरी क्षेत्रों में 10.2% से 45.5% तक बढ़ा, जिससे स्वास्थ्य सुरक्षा व उपचार तक पहुँच में सुधार हुआ है।
- NFHS-5 व NFHS-6 के बीच घरेलू बीमा कवरेज में 41.0% से 60.2% की वृद्धि हुई, जिससे जोखिम की साझेदारी और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच मजबूत हुई।
- प्रत्यक्ष स्वास्थ्य व्यय में 64.2% की गिरावट आई- जो कुल स्वास्थ्य व्यय का 43.4% था। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और वित्तीय सुरक्षा में सुधार का संकेत देता है।
- आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से परिवारों को जेब से होने वाले खर्च में ₹1.52 लाख करोड़ से अधिक की बचत हुई और स्वास्थ्य सेवाओं सुलभता बड़ी है।

- सरकारी स्वास्थ्य व्यय 2013-14 और 2022-23 के दौरान जीडीपी के 1.15% से 1.43% और कुल व्यय के 28.6% से 43.7% तक बढ़ा, जिससे वित्तपोषण और संस्थागत क्षमता में वृद्धि हुई है।
- 2013-14 और 2022-23 के दौरान सामाजिक सुरक्षा पर खर्च कुल स्वास्थ्य व्यय का 6%-9.9% तक बढ़ गया, जिससे जोखिम साझाकरण और स्वास्थ्य सेवाओं में समानता का विस्तार हुआ।

निष्कर्ष

भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहे बदलावों में सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक व्यापक पहुँच और परिवारों पर कम आर्थिक बोझ जैसी बातें तो हैं, लेकिन साथ ही पोषण, गैर-संचारी रोगों (NCD) और समानता से जुड़ी चुनौतियाँ भी अभी बनी हुई हैं।

6. राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के लिए अंतर्निहित ज्ञान का लाभ उठाना

परिचय

विकसित भारत 2047 का लक्ष्य जमीनी स्तर के नवाचार को आत्मनिर्भरता, समावेशी विकास तथा भारत के विविध सामुदायिक ज्ञान से जोड़ना है। राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान नागरिकों के ज्ञान को संस्थागत रूप देता है, जबकि यूनेस्को पारिस्थितिकीय परिदृश्यों को मान्यता प्रदान करता है।

निहित ज्ञान और भारत का नवाचार आधार

- औपचारिक अनुसंधान एवं विकास (R&D) अंतर्निहित ज्ञान, आवश्यकता, स्थानीय सामग्रियों और सरलता पर आधारित निरंतर जमीनी स्तर के नवाचार की अनदेखी करता है।
- भारत की लगभग पाँच सहस्राब्दी पुरानी सभ्यतागत निरंतरता कृषि, चिकित्सा, शिल्प, पारिस्थितिकी और पदार्थ विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय ज्ञान को संरक्षित रखती है।
- पीपुल ऑफ इंडिया परियोजना ने 4,635 समुदायों का दस्तावेजीकरण किया, जबकि पीपुल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ने देशभर में लगभग 780 भाषाओं की पहचान की।
- 1.45 अरब लोगों में से 730 से अधिक अनुसूचित जनजातियाँ मिलकर एक असाधारण रूप से विविध पारंपरिक ज्ञान भंडार का निर्माण करती हैं।
- अगरिया लोहार और केरल के ओडयिस और थाचन समुदायों ने विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्रों और व्यवसायों के अनुकूल तकनीकें विकसित कीं हैं।
- प्रोजेक्ट कौंडिन्य के अंतर्गत कील-रहित पोत ने जनवरी 2026 में पोरबंदर-मस्कट के लिए प्रस्थान किया और 18 दिनों की सफल समुद्री यात्रा पूरी की।

जैव विविधता, ज्ञान निष्कर्षण और संरक्षण

- भारत में दस जैव भौगोलिक क्षेत्रों में 45,000 पौधों और 91,000 जानवरों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो पृथ्वी के 2.4% हिस्से को कवर करती हैं।
- यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त पश्चिमी घाट, जो 38 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। इसमें 5,000 से अधिक पुष्पीय पौधे और 1,700 स्थानिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
- 1678-1693 तक, हेंड्रिक वैन रीड के हॉर्टस मालाबारिकस ने एझावा चिकित्सक इट्टी अचुदान पर काफी हद तक भरोसा किया।
- लीनियस ने इस ज्ञान का उपयोग स्पीशीज प्लांटारम (1753) में किया गया था, फिर भी मूल समुदायों को न तो मान्यता मिली, न अधिकार और न ही रिटर्न।
- मौखिक ज्ञान को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि बौद्धिक संपदा प्रणालियाँ समुदाय को श्रेय या मुआवजा दिए बिना ज्ञान का इस्तेमाल करने की सुविधा देती हैं।
- पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी पेटेंट अधिनियम की धारा 3(p) और पीएम विश्वकर्मा स्वदेशी ज्ञान संरक्षण को संस्थागत रूप देते हैं।

नागरिक-केंद्रित ढाँचा : खोज, सत्यापन, संरक्षण व प्रसार

- राज्य परिषदें, CRDTs, अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र, गुजरात ग्रासरूट्स इनोवेशन ऑग्मेंटेशन नेटवर्क (GIAN), सोसाइटी फॉर रिसर्च एंड इनिशिएटिव्स फॉर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज एंड इंस्टीट्यूशंस (SRISTI), पल्ले सृजना, योजक, सेवा एवं पीडीएस (PDS) पहुँच को मजबूत करते हैं।
- एनआईएफ के भंडार में पूर्व सूचित सहमति (PIC) सिद्धांतों का पालन करते हुए 730 जिलों में 3.75 लाख से अधिक विचार शामिल हैं।
- फैब लैब और विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला ने तकनीकों को प्रमाणित किया; एनआईएफ ने 1,478 पेटेंट आवेदन दाखिल किए, जिनमें से 725 को मंजूरी मिली।
- पौध किस्मों का संरक्षण और किसानों के अधिकारों का प्राधिकरण ने किसानों द्वारा विकसित 95 किस्मों में से 50 को पंजीकृत किया गया।
- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) समर्थित माइक्रो वेंचर इनोवेशन फंड (MVIF) ने 238 जमीनी स्तर की परियोजनाओं को वित्त पोषित किया।
- अट्ठाईस उद्यमों को उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग से मान्यता प्राप्त हुई, जिससे जमीनी स्तर पर उद्यमिता को मजबूती मिली।

निष्कर्ष

एनआईएफ समर्थित इनोवेटर्स ने 1,145 राष्ट्रीय सम्मान, लगभग बारह पद्म पुरस्कार और मन की बात में उल्लेख अर्जित किए हैं। इन नवाचारों के विस्तार के लिए परीक्षण और प्रमाणीकरण, सार्वजनिक खरीद, ग्रामीण आजीविका एकीकरण और सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) की आवश्यकता है।

7. भविष्य के लिए तैयार भारत के लिए शिक्षा एवं कौशल

परिचय

1.4 अरब की जनसंख्या वाले भारत में 65% से अधिक लोग 35 वर्ष से कम आयु के हैं। यह भारत को 2055 तक एक समय-सीमित जनसांख्यिकीय अवसर प्रदान करता है। 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शिक्षा सुधार के माध्यम से इस विशाल आबादी को कुशल मानव पूंजी में परिवर्तित करना आवश्यक है।

जनसांख्यिकीय अवसर और शिक्षा सुधार

- भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश 25-30 वर्षों तक उपलब्ध रहेगा; तथा भारत की काम करने वाली उम्र की आबादी 2047 तक एक अरब के करीब पहुँच सकती है।
- चीन में कार्यबल अपने चरम पर पहुँच चुका है, जबकि जापान और यूरोप बढ़ती उम्र की आबादी और श्रम की बढ़ती कमी का सामना कर रहे हैं।
- दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, चीन और जापान में शिक्षा में निवेश से औद्योगीकरण, तकनीकी उन्नति और उत्पादकता में वृद्धि देखी गई है।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 ने शिक्षा तक पहुँच बढ़ाई; राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 ने शिक्षण संरचना को बदल दिया।
- एनईपी बहुविषयक शिक्षा, डिजिटल शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, अनुसंधान-उन्मुख शिक्षा और मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देती है, हालाँकि गुणवत्ता और रोजगार क्षमता अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है।
- शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किए जाने से केंद्र-राज्य-उद्योग समन्वय की आवश्यकता उत्पन्न होती है। विकसित भारत@2047 : युवाओं की आवाज सहभागिता को बढ़ावा देती है।

सार्वजनिक निवेश और संस्थागत समन्वय

- शिक्षा के लिए आवंटन में वृद्धि हुई : ₹93,224.48 करोड़ (2021-22), ₹1,21,118 करोड़ (2024-25), और ₹1,28,650 करोड़ (2025-26)।
- 2026-27 में आवंटन ₹1,39,289.48 करोड़ तक पहुँच गया, जो सालाना 8.27% और पाँच वर्षों में लगभग 50% की वृद्धि दर्शाता है।
- स्कूली शिक्षा को 83,562 करोड़ रुपये प्राप्त हुए; उच्च शिक्षा को 55,727.22 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जिसमें मूलभूत शिक्षा, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता दी गई।
- निर्मला सीतारमण ने शिक्षा से रोजगार और पर एक स्थायी समिति की घोषणा की, जिसकी अध्यक्षता नीति आयोग के सीईओ करेंगे।
- इस समिति का लक्ष्य 2047 तक वैश्विक सेवाओं की हिस्सेदारी को दोगुना करना और औद्योगिक-लॉजिस्टिक्स गलियारों के पास पाँच विश्वविद्यालय टाउनशिप स्थापित करना है।

भविष्य के कौशल और रोजगार क्षमता

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), रोबोटिक्स, स्वचालन, जलवायु प्रौद्योगिकी, विश्लेषण, मशीन लर्निंग और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में उद्योग-अनुरूप पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है।
- अमेरिका और चीन एआई में भारी निवेश कर रहे हैं; फरवरी 2026 में आयोजित भारत एआई इम्पैक्ट समिट ने समावेशी ग्लोबल साउथ नेतृत्व को बढ़ावा दिया।
- भारत की सूचना प्रौद्योगिकी (IT), परामर्श और आउटसोर्सिंग की क्षमताएँ सेमीकंडक्टर, हरित ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, जैव प्रौद्योगिकी, फिनटेक व डिजिटल नवाचार को समर्थन प्रदान करती हैं।
- आलोचनात्मक चिंतन, रचनात्मकता, संचार, टीम वर्क, अनुकूलन क्षमता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, नेतृत्व और समस्या-समाधान जैसी क्षमताएँ अपरिहार्य मानवीय क्षमताएँ बनी हुई हैं।
- शिक्षा और रोजगार के बीच असंगति अभी भी बनी हुई है। स्किल इंडिया मिशन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) ने विभिन्न क्षेत्रों में लाखों लोगों को प्रशिक्षित किया है।
- राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (NAPS) कार्यस्थल पर सीखने का विस्तार करता है तथा एनईपी व्यावसायिक शिक्षा और आजीवन कौशल विकास को मुख्यधारा में लाता है।

निष्कर्ष

भारत की जनसांख्यिकीय क्षमता अस्थायी है इसलिए शिक्षा और उद्योग के बीच प्रभावी समन्वय, रोजगारोन्मुख कौशल विकास तथा आजीवन सीखनेकी संस्कृति को बढ़ावा देकर ही भारत अपनी विशाल जनसंख्या को कुशल मानव पूंजी, रचनात्मकता और सतत विकास की शक्ति में बदल सकता है।

8. सतत विकास : प्रकृति में निहित ज्ञान

परिचय

भारत की सतत विकास की परंपरा में सभ्यतागत नैतिकता, पुनर्योजी विकास, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) और सामुदायिक जल संरक्षण का संयोजन है।

स्थिरता की सभ्यतागत नींव

- भारतीय सतत विकास की अवधारणा शुभ-लाभ, सनातन निरंतरता और सतत विकास का मेल है जो समृद्धि को पारिस्थितिक संयम के साथ जोड़ती है।
- अथर्ववेद पृथ्वी को पवित्र मानता है और स्वार्थ के कारण पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने के खिलाफ आने वाली पीढ़ियों के प्रति जिम्मेदारी का भाव जगाता है।

- प्रकृति बच्चों से उधार ली गई है; इसलिए इसका संरक्षण एक नैतिक ऋण और सभ्यतागत कर्त्तव्य बन जाता है।
- 1991 में पेरिस सम्मेलन की तैयारियों और 1992 में रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान स्थिरता को वैश्विक स्तर पर महत्त्व मिला।
- पुनर्योजी विकास बिना विनाश, क्षरण या विस्थापन के बिना सृजन की अनुमति देता है, जिससे प्रकृति की नवीकरण क्षमता संरक्षित रहती है।

विकास और नीतिगत प्राथमिकताएँ

- जल संरक्षण हरियाली को बहाल करता है, कार्बन अवशोषण को बढ़ाता है, मिट्टी में सुधार करता है और व्यवहारिक परिवर्तन के माध्यम से जलवायु अनुकूलन को मजबूत करता है।
- उद्योग को पारिस्थितिक वहन क्षमता का सम्मान करना चाहिए, रिड्यूस- रियूज-रिसायकल के सिद्धांत को अपनाना चाहिए, पर्यावरणीय क्षरण की भरपाई करनी चाहिए और संसाधन-कुशल स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना चाहिए।
- वर्ष 2000 तक जनसंख्या लगभग छह अरब तक पहुँच गई थी; पचास वर्षों के भीतर ग्यारह अरब होने का अनुमान था, जबकि एक चौथाई लोग प्रतिदिन 1 डॉलर से कम पर जीवन यापन करते थे।
- प्राथमिकताओं में पेयजल, कृषि योग्य भूमि, भोजन, मातृ मृत्यु दर में 75% की कमी और दक्षता के साथ नवीकरणीय ऊर्जा तक पहुँच शामिल थी।
- कृषि विस्तार वनों की कटाई को बढ़ावा देता है; पारिस्थितिक सुरक्षा के लिए वनों का पुनर्स्थापन और बेहतर प्रबंधन आवश्यक बना हुआ है।
- राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC) 30 जून 2008 को आठ मिशनों के साथ शुरू किया गया; कृषि-उद्योग में इसका कार्यान्वयन 2024 तक शुरू हो गया।

सामुदायिक कार्रवाई और पारिस्थितिक शासन

- पर्यावरण शिक्षा नीति निर्माण में पृथ्वी-केंद्रित सोच को शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही, अंतरपीढ़ीगत समानता और नागरिक भागीदारी को भी एकीकृत किया जाना चाहिए।
- सरकारों को सार्वजनिक-निजी निर्णयों में स्थिरता को मुख्यधारा में लाना होगा, और अल्पकालिक उपायों के स्थान पर दीर्घकालिक पारिस्थितिक योजना अपनानी होगी।
- तरुण भारत संघ ने 51 वर्षों के दौरान 15,000 से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण किया, जिससे 1,500 गाँवों को सुरक्षा प्रदान की गई।
- सामुदायिक बहाली के प्रयासों से राजस्थान की कई नदियों में फिर से जान आ गई, जिनमें अरवरी, रूपारेल, सरसा, महेश्वरा, साबी, तेवर, सैरनी, पार्वती, नौरा, भवानी और कोटवारी शामिल हैं।
- महाराष्ट्र की अग्रणी और महाकाली नदियों के साथ-साथ कर्नाटक की इचनहल्ला नदी में भी प्राकृतिक जल-प्रवाह फिर से बहाल हुआ।
- इससे 10,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को लाभ हुआ, जो जलवायु अनुकूलन और जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने के मिले-जुले प्रयासों से समुदाय के नेतृत्व में की गई बहाली का एक बेहतरीन उदाहरण है।

निष्कर्ष

सतत विकास के लिए सरकारों, बाजारों, समुदायों एवं पीढ़ियों के बीच पर्यावरण के पुनर्निर्माण, जिम्मेदार समृद्धि और सामूहिक देखभाल की जरूरत है।

9. प्रोजेक्ट वीर गाथा : विरासत से नागरिक चेतना तक

परिचय

वीर गाथा परियोजना को 2021 में शिक्षा एवं रक्षा मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से वीरता पुरस्कार पोर्टल (GAP) के तहत शुरू किया गया, जो वीरता को नागरिक चेतना में परिवर्तित करता है।

मूल्य एवं शैक्षिक पद्धति

- साहस एवं बलिदान की कहानियाँ मूल्यों पर आधारित एक व्यवस्थित शिक्षण पद्धति बन जाती हैं, जो अनुशासन, जिम्मेदारी और नागरिक चेतना को बढ़ावा देती हैं।
- देशभक्ति का विकास केवल युद्ध के मैदान की वीरता से नहीं, बल्कि कक्षा में चिंतन, जागरूकता और नैतिक समझ से होता है।
- छत्रपति शिवाजी महाराज, कैप्टन विक्रम बत्रा और अज्ञात रक्षकों ने भारत की निरंतर चली आ रही सभ्यतागत विरासत का प्रतिनिधित्व किया।
- निबंध, कविता, कहानी सुनाना, कला का एकीकरण, रिपोर्टिंग और डिजिटल अभिव्यक्ति रटकर सीखने की बजाय चिंतनशील भागीदारी को बढ़ावा देती हैं।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 नैतिक नागरिकता पर आधारित विकासात्मक, संवेदनशील और रचनात्मक शिक्षा का समर्थन करता है।
- भारतीय ज्ञान प्रणाली (IKS) संवैधानिक मूल्य और क्षेत्रीय आख्यान विरासत को एक सक्रिय परंपरा के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

संस्थागत पहुँच और भागीदारी

- प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मायगॉव (MyGov) और वीरता पुरस्कार विजेताओं को आपस में जोड़ता है।

- इसमें भाग लेने वाले छात्रों की संख्या 2021-22 में आठ लाख से बढ़कर 2025-26 में 1.92 करोड़ हो गई, जो चौबीस गुना वृद्धि को दर्शाता है।
- इसके दायरे में वीरता पुरस्कार विजेता, 'समर परंपरा', ऐतिहासिक युद्ध, रणनीतिक सोच और अलग-अलग दौर के योद्धा शामिल हैं।
- गणतंत्र दिवस की गतिविधियाँ और शिक्षकों के मार्गदर्शन में बने 'वीर गाथा कॉर्नर' संस्थागत यादों को संजोते हैं और नागरिकों की भागीदारी को मजबूत करते हैं।
- कक्षा 3 से 12 तक के छात्र स्कूल-स्तर के तय माध्यमों से रिसर्च करते हैं, रचनाएँ बनाते हैं और अपनी प्रविष्टियाँ जमा करते हैं।

मूल्यांकन और व्यापक अधिगम

- बहुस्तरीय मूल्यांकन में स्कूल, जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर शामिल होते हैं जिसके आधार पर सुपर 100 का चयन किया जाता है।
- मूल्यांकन में मौलिकता एवं विषयगत प्रासंगिकता को प्राथमिकता दी जाती है। साथ ही समझ, स्पष्टता और मूल्य-आधारित चिंतन को भी महत्त्व दिया जाता है।
- भविष्य के विस्तार में डिजिटल कहानी कहने, क्षेत्रीय नायकों, बहुभाषी अनुसंधान और अंत:विषयक नागरिक शिक्षा पर जोर दिया गया है।
- अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सतत विकास 2030 के लिए शिक्षा और वैश्विक नागरिकता शिक्षा विरासत को वैश्विक शिक्षा से जोड़ती है।

निष्कर्ष

राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर आधारित यह मिशन, विकसित भारत@2047 के लिए ऐतिहासिक स्मृति को जिम्मेदार नागरिकता से जोड़ता है।

10. आंतरिक संतुलन, बाहरी चमक

परिचय

योग सौंदर्य को आंतरिक संतुलन की अभिव्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है, जो समग्र कल्याण के लिए आसन, श्वास और ध्यान को संयोजित करता है।

योग और समग्र स्वास्थ्य

- योग में गति, श्वास, विश्राम और ध्यान का एकीकरण होता है, जो शारीरिक स्फूर्ति, भावनात्मक संतुलन और मानसिक शांति को बढ़ावा देता है।
- नियमित योग अभ्यास से रक्त संचार, शारीरिक मुद्रा और लचीलापन बेहतर होता है। साथ ही, तनाव और गतिहीन जीवनशैली से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी जोखिम कम होते हैं।
- अच्छी सेहत केवल बाहरी दिखावट को नहीं दर्शाती, बल्कि शरीर, मन और भावनाओं के बीच संतुलन को भी प्रतिबिंबित करती है।
- योग स्वस्थ आदतों को बढ़ावा देता है जो खान-पान, पानी की मात्रा, नींद और जीवनशैली पर असर डालती हैं, जिससे त्वचा की सेहत बनी रहती है।
- बेहतर रक्त संचार ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को कुशलतापूर्वक शरीर में पहुँचाता है, जिससे त्वचा और बालों को प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहने में मदद मिलती है।

श्वास, सचेतनता और भावनात्मक संतुलन

- शारीरिक मुद्राएँ मांसपेशियों की टोन, लचीलापन और रीढ़ की हड्डी के संरेखण में सुधार करती हैं, जिससे शरीर के प्रति जागरूकता और सहज गति मजबूत होती है।
- प्राणायाम सांस लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, तंत्रिका तंत्र को शांत करता है और भावनात्मक संतुलन, एकाग्रता व बेहतर नींद में सहायक होता है।
- सचेतनता वर्तमान क्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाता है, ध्यान भटकाने वाली चीजों को कम करता है और मुँहासे और संवेदनशीलता जैसी तनाव संबंधी त्वचा समस्याओं को नियंत्रित करने में मदद करता है।
- ध्यान और सचेत श्वास क्रिया मानसिक शांति, आत्मविश्वास और आत्म-जागरूकता को बढ़ावा देते हैं, जिससे व्यक्तित्व और समग्र सौंदर्य में निखार आता है।

स्वस्थ वृद्धावस्था और आंतरिक चमक

- योग शरीर के लचीलेपन, जोड़ों की गतिशीलता, मांसपेशियों की शक्ति और शारीरिक आत्मविश्वास को बनाए रखकर स्वस्थ वृद्धावस्था में सहायक होता है।
- तनाव प्रबंधन और विश्राम से भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार होता है, जिससे बुजुर्ग सक्रिय और ऊर्जावान बने रहते हैं।
- अच्छी मुद्रा आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को आकार देती है, जबकि रीढ़ की हड्डी का संरेखण और संतुलन सहज और आकर्षक गतिशीलता प्रदान करते हैं।
- नियमित योगाभ्यास अनुशासन और शांति को दर्शाता है, जिससे बाहरी आभा और सकारात्मक व्यक्तित्व के रूप में दिखाई देता है।
- शरीर, मन और भावनाओं के सामंजस्य से ही स्थायी सौंदर्य उत्पन्न होता है, और आंतरिक कल्याण का प्रभाव बाहर की ओर प्रतिबिंबित होता है।

निष्कर्ष

योग को जीवनशैली का हिस्सा बनाने से जीवन शक्ति, आत्मविश्वास और शांति का विकास होता है, जिससे आंतरिक स्वास्थ्य शाश्वत सुंदरता को आकार देता है।